this context I would like to ask the hon. Minister or the Prime Minister whether the Government has made any effort to export automobile parts. If so, to which country and what was its volume in terms of dollars and rupees during the year 1992-93?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pending cases in Supreme Court relating to reservation of SC/STs

*422. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of cases relating to reservation of SC/STs pending in Supreme Court, as on 1-8-1993, for more than one year, for more than five years, for more than ten years and for more than fifteen years, separately;

(b) whether the Supreme Court proposes to constitute a special bench for deciding all the matters relating to reservation of SC/STs within a limited period keeping in view the Government policy; and

(c) the total number of Government counsels at present for Supreme Court working on behalf of Central Government and number of SC/STs therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) As per the information made available by the Registry of the Supreme Court, 83 cases relating to reservation of SCs/STs were pending as on 1st August, 1993. The break-up is as follows:

More than 1 year	—	83 cases
More than 5 years	—	80 cases
More than 10 years	—	63 cases
More than 15 years	—	1 case

(b) The above matters are already before the Constitution Bench of the Supreme Court.

(c) Of the 10 full time Advocates working for the Government in the Supreme Court, one belongs to SC category.

गुजरात में बंजर भूमि के विकास संबंधी स्वैच्छिक एजेंसियों का पता लगाया जाना

*426. श्री रामसिंह राठवा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास संबंधी स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनकी सेवाओं का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये इन स्वैच्छिक संगठनों के पूर्व कार्यों की समीक्षा की है कि कहीं इन संगठनों के विरुद्ध विगत में सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें तो नहीं की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास) में राज्य मंत्री (श्री कमल राम सिंह): (क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत गुजरात सहित देश में बंजर भूमि के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों का पता लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, बंजर भूमि के विकास के लिए सहायता चाहनेवाले स्वैच्छिक संगठन अपनी ओर से राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को आवेदनपत्र देते हैं और अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें गुजरात के संगठन भी शामिल हैं, से अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों की टिप्पणी प्राप्त कर लेने के बाद अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुदान-सहायता योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन की भी व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संगठनों को रिलीज की गई धनराशि का समुचित ढंग से उपयोग किया गया है।

Ban on Benzidine and Benzidine-based Dyes

*427. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the manufacture, marketing and use of Benzidine and Benzidine-based dyes were banned with effect from January 31, 1993 on account of their carcinogenic nature;

(b) whether it is also a fact that despite the Government giving more than three years time before imposing the ban to the manufacturers and users, Benzidine-based dues continue to be manufactured, sold and used even after the ban has become effective; and